जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

जालोर

Rashtradoot

फोनः- 226422, 226423 फैक्सः- 02973-226424 वर्षः 20 संख्याः 99 प्रभात जालोर, बुधवार 16 जुलाई, 2025 पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2022-24 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

ट्रंप, 30 प्रतिशत चीन के, 35 प्रतिशत कैनडा के, 25 प्रतिशत मैक्सिको के निर्यात पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने जा रहे हैं

इन देशों पर लगे इस भारी टैरिफ के कारण ''प्राइस वॉर'' में भारत इन देशों की तुलना में सस्ता हो जाता है और भारत को अमेरिका को निर्यात की मुख्य 30 कैटिगरी में से 22 में भारी लाभ होगा

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15 जुलाई। वैश्विक व्यापार में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है, और भारत इसके सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक बन सकता है। अमेरिका चूंकि चीन, मैक्सिको और कनाडा जैसे प्रमुख व्यापार साझेदारों पर टैरिफ बढ़ा रहा है, इसलिए भारतीय निर्यातकों को बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने का एक दुर्लभ रणनीतिक अवसर मिल रहा है-विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन और वस्त्र जैसे क्षेत्रों में।

- इन 30 कैटेगरी में लगभग 2.28 ट्रिलियन डॉलर का निर्यात का धंधा होता है।
- ये अधिकतर लाभ कैमिकल्स, फार्मास्युटिकल्स, वस्त्र (टैक्सटाइल्स), आईटी सर्विसेज़ में होगा, जहाँ भारत अभी भी इन देशों से कुछ सस्ता है और यदि अमेरिका अतिरिक्त टैरिफ लगा देता है, जैसे इन देशों को आशंका है, तो भारत की बल्ले-बल्ले स्थिति हो जाती है।
- पर, नीति आयोग की पत्रिका, ट्रेड वॉच क्वार्टर्ली के आँकड़ों के अनुसार, भारत की इस बल्ले-बल्ले स्थिति के साथ-साथ संकट की भी आशंका है। छः कैटिगरियों में भारत का माल 1 से तीन प्रतिशत महँगा भी हो सकता है। विशेषकर कृषि, डेयरी तथा ऑटोमोबाइल सैक्टर में। उदाहरण के लिए, अगर भारत डेयरी सैक्टर में दूध पर टैरिफ कम कर देता है तो भारत में इसकी कीमत 15 प्रतिशत टूट जाएगी, तथा भारत के दुग्ध उत्पादकों को प्रतिवर्ष 1 लाख करोड़ रूपये का नुकसान उठाना पड़ेगा।

नीति आयोग की नवीनतम ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट के अनुसार, भारत वैश्विक व्यापार की शीर्ष 30 श्रेणियों (एच एस 2-स्तर) में से 22 में प्रतिस्पर्धात्मकता हासिल करने के लिए तैयार है, जो 2.28 ट्रिलियन से अधिक के बाजार का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसका बड़ा कारण ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाया गया टैरिफ ब्लिट्ज है-चीनी आयात पर 30 प्रतिशत, कनाडाई वस्तुओं पर 35 प्रतिशत और मैक्सिकन उत्पादों पर 25 प्रतिशत। इन अधिक शुल्कों ने भारतीय उत्पादों को अमेरिकी बाजार में अपेक्षाकृत सस्ता और आकर्षक बना दिया है।

एसबीआई की नवीनतम व्यापार दृष्टिकोण रिपोर्ट भी इसी आशावाद को दर्शाती है। भले ही भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते से नई दिल्ली को सभी अपेक्षित लाभ न मिलें, पर भारत के पास आगे बढ़ने के विकल्प हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर 10 प्रतिशत का काल्पनिक टैरिफ भी लगा दे, तब भी भारत का निर्यात प्रभावित नहीं होगा-जो 2024-25 में रिकॉर्ड 387.5 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया, विशेष रूप से आईटी, वित्तीय और व्यावसायिक सेवाओं के बल पर।

नीति आयोग रिपोर्ट के अनुसार ''वैश्विक टैरिफ परिदृश्य बदल रहा है, और भारत को इन बदलावों का फायदा तेजी से उठाना चाहिए,'' सबसे बड़ा लाभ उन क्षेत्रों में हो सकता है जहां भारत को पहले से ही रीवील्ड कम्पैरेटिव एडवांटेड (आरसीए) प्राप्त है-जो निर्यात प्रतिस्पर्धा का एक प्रमुख आर्थिक मापदंड है।

उदाहरण के लिए, रसायन क्षेत्र में भारत को आरसीए प्राप्त है, जहां फिलहाल चीन और सिंगापुर अमेरिकी आयात पर हावी हैं। लेकिन चीन पर भारी टैरिफ लगने से भारत इस क्षेत्र में जगह बना सकता है। यदि भारत चीन और

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'ट्रेनी एसआई का टैस्ट जाँच का हिस्सा था'

जयपुर, 15 जुलाई। एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक प्रकरण में अदालती आदेश की पालना में एसआईटी के मुखिया वीके सिंह हाईकोर्ट में पेश हुए। इस दौरान, अदालत ने केस से जुड़े वकीलों के अलावा अन्य सभी को बाहर जाने का कहकर, वीके सिंह से सवाल-जवाब किए। इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 17 जुलाई को रखी है।

- एसआईटी प्रमुख ने हाई कोर्ट को एसआई पेपर लीक के बारे में अपडेट दिया।

वीके सिंह ने अदालत से कहा कि ट्रेनी एसआई की परीक्षा छंटनी के लिए नहीं, बल्कि जांच का हिस्सा थी। इसके जरिए अभ्यर्थियों की बौद्धिकता का

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बारिश का अनुमान

जयपुर, 15 जुलाई। मौसम विभाग ने राजस्थान में 16 व 17 जुलाई को कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने 16 जुलाई को बांरा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ , झालावाड़, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर व श्रीगंगानगर में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसी प्रकार 17 जुलाई को भी बांरा, बूंदी, झुंझूनूं, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, चूरू में भारी बारिश की चेतावनी दी है।

महाराष्ट्र भी शीघ्र ही जबरन ''धर्म परिवर्तन'' विरोधी कानून लाएगा

पर, महाराष्ट्र का कानून अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा सख्त है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15 जुलाई। महाराष्ट्र देश का ऐसा ग्यारहवां राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, जो धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करेगा। देवेन्द्र फड़नवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में यह विधेयक विधानसभा में पेश करने की तैयारी कर रही है।

- ऐसा माना जाता है कि यह प्रस्तावित ''लव जिहाद'' पर तो रोक लगायेगा, साथ ही ईसाई धर्म परिवर्तन पर भी अंकुश लगायेगा।
- महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री ने विधानसभा में कहा, ''ईसाई, विदेशों से आए पैसों से आदिवासी इलाकों में हजारों चर्च बना रहे हैं, तथा 2000 लोगों के गाँव में भी एक दर्जन से भी ज्यादा चर्च बन गये हैं तथा प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है।
- मंत्री ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा अगले महीनों में अनाधिकृत तरीके से बनाये गये ये चर्च तोड़ दिये जायेंगे।

राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, झारखंड और उत्तराखंड सहित, दस राज्य पहले ही धर्मांतरण विरोधी कानून लागू कर चुके हैं। इनका मुख्य उद्देश्य मोटे तौर ''लव जिहाद'' को रोकना रहा है। महाराष्ट्र के मामले में, प्रस्तावित कानून का दायरा व्यापक प्रतीत होता है, जिसमें ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों को भी शामिल किया गया है, जो कथित रूप से विदेशी फंडिंग का उपयोग करके आदिवासियों का धर्मांतरण कर रही हैं और अवैध चर्च बना रही हैं।

पिछले सप्ताह, महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा था कि धर्मांतरण को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में बने अवैध चर्चों को अगले छह महीनों के भीतर ध्वस्त कर दिया जाएगा।

सोमवार को विधानसभा में बोलते हुए, गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने कहा कि राज्य सरकार आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाने की तैयारी कर रही है और इसके प्रावधान अन्य राज्यों के इसी प्रकार के मौजूदा कानूनों की तुलना में अधिक सख्त होंगे।

यह घोषणा इसलिए और अधिक महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि यह गृह राज्य मंत्री की ओर से आई है।

राज्य सरकार ने ऐसे कानून के मसौदे को तैयार करने के लिए पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जा चुकी है।

फड़नवीस सरकार की यह पहल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल ने पहलगाम हमले में सुरक्षा चूक की बात मानी

पहलगाम हमले के 82 दिन बाद आई इस स्वीकारोक्ति को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15 जुलाई। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा पहलगाम में सुरक्षा चूक की सार्वजनिक स्वीकारोक्ति और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की विवादित नज़रबंदी के बाद केंद्र सरकार गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है। इन घटनाओं ने इस संवेदनशील क्षेत्र में नैतिक और प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

- उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की उक्त स्वीकारोक्ति और फिर अगले दिन ही मुख्यमंत्री को शहीदों की श्रद्धांजलि सभा में जाने से रोकने के लिए नज़रबंद किए जाने से राजनैतिक हलकों में भारी खलबली मच गई है।

श्रीनगर में पर्यवेक्षक तब हैरान रह गए जब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक अप्रत्याशित बयान में पहलगाम की घटना को लेकर सुरक्षा तंत्र में खामियों को स्वीकार किया। सिन्हा पिछले तीन वर्षों से जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल हैं और इस तरह की स्पष्ट प्रशासनिक विफलता की स्वीकारोक्ति को बेहद दुर्लभ माना जा रहा है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सिन्हा का बयान सोची-समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। घटनाक्रम से परिचित सूत्रों के अनुसार, यह बयान पूरी तरह से स्वाभाविक नहीं था, बल्कि दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारियों से विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया था, जिससे जनता का ध्यान केंद्र सरकार से हटाया जा सके और ऑपरेशनल विफलता का दोष उपराज्यपाल के कार्यालय की ओर मोड़ा जा सके।

इस विवाद को और गहरा करते हुए, नैशनल कॉन्फ्रैंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को उपराज्यपाल सिन्हा के बयान के ठीक एक दिन बाद नज़रबंद कर दिया गया। अब्दुल्ला श्रीनगर में एक कब्रिस्तान में शहीदों की सार्वजनिक श्रद्धांजलि सभा में भाग लेने जा रहे थे, जिसे रोकने के लिए उन्हें नजरबंद कर दिया गया। पहले भी कई राजनीतिक नेताओं को नजरबंद किया गया था, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को भी इस तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

इन दोनों घटनाओं के समय ने सवाल खड़े कर दिए हैं। विश्लेषकों का कहना है कि उपराज्यपाल सिन्हा की प्रतिक्रिया पहलगाम घटना के 82 दिन बाद आई, जो इस ओर इशारा करती है कि यह बयान दिल्ली से स्पष्ट निर्देश मिलने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राहुल गांधीः सरैन्डर और जमानत

लखनऊ, 15 जुलाई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मानहानि के एक मामले की सुनवाई के लिए मंगलवार को लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया। लेकिन 5 मिनट के बाद ही राहुल को जमानत मिल गई। एडिशनल सीजेएम आलोक वर्मा वाली एमपी एमएलए कोर्ट ने 20 हजार रुपये के दो बॉन्ड पर उन्हें जमानत दे दी। बता दें कि यह मामला 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान

- सैनिकों पर एक टिप्पणी को लेकर दायर मान हानि मामले में मंगलवार को राहुल गांधी लखनऊ के एमपीएमएलए कोर्ट में उपस्थित हुए, जहाँ उन्होंने आत्मसमर्पण किया और 5 मिनट बाद उन्हें जमानत मिल गई।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 1000 से ज्यादा असिस्टैंट प्रोफेसरों की भर्ती रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस भर्ती में यूजीसी के निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब सरकार द्वारा 2021 में की गई 1,158 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसरों और लाइब्रेरियनों की नियुक्तियों को, यूजीसी नियमों के उल्लंघन के आधार पर, रद्द कर दिया। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की डिवीजन बैंच के भर्ती प्रक्रिया को सही ठहराने के फैसले को रद्द कर दिया।

- सुप्रीम कोर्ट ने यह भर्ती रद्द करने के पंजाब, हरियाणा हाई कोर्ट की सिंगल बैंच के फैसले को सही ठहराया और फैसले में डिविज़न बैंच के हस्तक्षेप को गलत करार दिया।

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने यह फैसला उन कई याचिकाओं पर सुनाया, जिनमें हाई कोर्ट की डिवीज़न बैंच के भर्ती प्रक्रिया को सही ठहराने के फैसले को चुनौती दी गई थी।

कोर्ट ने कहा, ''इस मामले में कई कमियां हैं, जैसे यूजीसी के नियमों में निर्धारित मानकों को हटाकर, केवल एक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र आधारित लिखित परीक्षा कराना और मौखिक परीक्षा को पूरी तरह से समाप्त करना आदि, तथा इसलिये पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के एकल न्यायाधीश द्वारा पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द किया जाना सही निर्णय था, और डिवीज़न बैंच ने उस निर्णय में हस्तक्षेप करके गलती की।''

जनवरी 2021 में पंजाब सरकार ने पंजाब लोक सेवा आयोग (पीपीएससी) से 931 असिस्टेंट प्रोफेसरों और 50 लाइब्रेरियनों की भर्ती कराने के लिए अनुरोध किया था। बाद में, सरकार ने नए स्थापित कॉलेजों के लिए 160 असिस्टेंट प्रोफेसरों और 17 लाइब्रेरियनों की अतिरिक्त भर्ती की भी मंजूरी दी।

लेकिन सितंबर-अक्टूबर 2021 में सरकार बदलने के बाद, प्रक्रिया को बदल दिया गया और पीपीएससी को दरकिनार करते हुए, दो विभागीय चयन समितियों के माध्यम से 1,091 असिस्टेंट प्रोफेसर और 67 लाइब्रेरियन पदों की भर्ती करने का निर्णय लिया गया। इन समितियों के अध्यक्ष राज्य के दो विश्वविद्यालयों के वाइस-चांसलर थे।

यह मामला पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एकल न्यायाधीश के समक्ष आया, जिसने अगस्त 2022 में पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया।

बाद में, पंजाब सरकार और चयनित अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में डिवीज़न बैंच के समक्ष अपील की, जिसने सितंबर 2024 में एकल न्यायाधीश के निर्णय को पलट दिया और भर्ती को वैध ठहराया।

इस फैसले से असन्तुष्ट याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने एकल न्यायाधीश के फैसले को बहाल करते हुए, पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि इन पदों के लिए यूजीसी के 2018 के नियमों के अनुसार नये सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरु की जाये।

स्वर्ण मंदिर को 24 घंटे में दूसरी बार बम की धमकी

अमृतसर (पंजाब), 15 जुलाई। पंजाब के अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर (हरमिंदर साहिब) को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, 24 घंटे में दूसरी ईमेल के जरिये यह धमकी मिली है। इसके बाद जिला शहरी पुलिस की तरफ से स्वर्ण मंदिर और आस-पास सुरक्षा पहले से भी ज्यादा कड़ी कर दी है। हरमिंदर साहिब के आने-जाने वाले हर एक रास्ते को सील कर दिया है और हर श्रद्धालु की

- दूसरे दिन फिर से स्वर्ण मंदिर को बम से उड़ाने का धमकी भरा ई-मेल आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसी के साथ पुलिस ई-मेल का उद्गम ट्रेस करने का प्रयास भी कर रही है।

चैकिंग की जा रही है। पंजाब पुलिस के साथ-साथ बीएसएफ को भी तैनात किया गया। वहीं इसके अलावा पूरे इलाके में डॉग और बम स्क्वॉड भी तैनात कर दिए गए हैं। जानकारी मुताबिक एसजीपीसी को भेजी गई ईमेल में लिखा गया है कि हरमिंदर साहिब के आस-पास की पाइपों में आरडीएक्स भर दिया गया है। जिससे अंदर धमाके किए जाएंगे। हालांकि, सुरक्षा कारणों से न तो मेल और न ही उसमें लिखे गए शब्दों को सार्वजनिक किया गया है।

यमन में भारतीय नर्स की मौत की सजा टली

नयी दिल्ली,15 जुलाई। यमन में हत्या के जुर्म में जेल में बंद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को दी जाने वाली मौत की सज़ा भारत सरकार के प्रयासों के बाद टाल दी गई है।

सूत्रों ने मंगलवार को यहां बताया कि भारतीय अधिकारियों के प्रयासों से निमिषा प्रिया की सजा फिलहाल स्थगित हो गई है। भारतीय अधिकारी वहां के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में थे। सूत्रों ने कहा, पता चला है कि यमन के स्थानीय अधिकारियों ने 16 जुलाई को निमिषा प्रिया को दी जाने वाली मौत की सज़ा टाल दी है। भारत सरकार इस

- भारत सरकार के प्रयासों की वजह से यह सफलता मिली है। खबर है कि निमिषा को माफी देने के लिए 8.5 करोड़ रु. देने की पेशकश की गई है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'पुतिन औपचारिक बातचीत में तो बहुत अच्छी बात करते हैं, पर, शाम होते ही सब पर बमबारी शुरु कर देते हैं'

ट्रंप ने अब स्वीकार कर लिया है, रूस के साथ ''डिप्लोमैसी'' (कूटनीति) सफल नहीं हो रही, इसलिए अब, दादागिरी वाला सख्त रुख अपनाया

-अंजन रॉय-
-अमेरिका में राष्ट्रदूत के प्रतिनिधि-

नई दिल्ली, 15 जुलाई। यूक्रेन युद्ध रोकने की ट्रंप की नई पॉलिसी के तहत भारत को अमेरिका से एक नए टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है, जो 100 प्रतिशत तक हो सकती है।

एक नया विधेयक अमेरिकी विधायिका (यू.एस. लैजिस्लेचर) में पारित होने की प्रक्रिया में है, जो रूस के खिलाफ सैकेण्डरी सैंक्शन्स (परोक्ष प्रतिबंध) लगाने का प्रावधान करता है, ताकि देश को युद्ध जारी रखने से रोका जा सके। प्रस्ताव में 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने का प्रावधान है, जो चुनिंदा रूप से भारत और चीन पर लक्षित है, ये दोनों देश रूसी तेल के प्रमुख खरीदार हैं।

चीन और भारत की संयुक्त खरीद, जो अरबों डॉलर में है, ने एक तरह से रूस को उसके युद्ध को जारी रखने में मदद की है। तेल राजस्व से वंचित होने पर, रूस का युद्ध प्रयास तुरंत ढह सकता है। रूस अपने युद्ध प्रयासों की फंडिंग के लिए तेल राजस्व पर निर्भर है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था सिकुड़ चुकी है।

तीन साल से अधिक समय से चल रहे युद्ध के कारण रूस कई समस्याओं का सामना कर रहा है। सी.एन.एन. की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रत्यक्ष सैन्य खर्च लगभग 300 बिलियन डॉलर आँका गया है। इसके अलावा, रूस की विदेशी संपत्तियाँ, जो अरबों में हैं, को पश्चिमी देशों ने फ्रीज़ किया हुआ है।

पश्चिम के कई लोगों ने सुझाव दिया है कि फ्रीज़ किए हुए रूस के इन रिज़र्व्ज़ को युद्ध के कारण तबाह हुए यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया जाए। ये फंड रूस की पहुँच से बहुत दूर हैं। रूसी बैंकों पर प्रतिबंधों ने अन्य देशों के साथ रूसी तेल के गुप्त लेन-देन (शैडो ट्रांज़ैक्शन) को काफी हद तक सीमित कर दिया है।

इसके अलावा, यूक्रेन युद्ध में भारी हताहतों तथा और अधिक सैनिकों की माँग ने रूसी अर्थव्यवस्था के लिए मैनपावर के आधार को कम कर दिया है। तैनाती के लिए मैनपावर की इतनी भारी भर्ती की गई है कि रूसी जेलों से रिहा किए गए अपराधियों तक को लड़ाई के लिए सेना में शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा, यूक्रेन में लड़ने के लिए रूस विदेशों से सैनिक ला रहा है। उत्तर कोरिया और अन्य विभिन्न देशों से, जिनमें चीन भी शामिल है, लाए गए सैनिक यूक्रेन में देखे गए हैं और यूक्रेन में कभी-कभी पकड़े भी गए हैं।

युद्ध करने योग्य जनसंख्या में से की जा रही मजदूरों की भर्ती का असर अब रूस की फैक्टरियों में श्रमिकों की आपूर्ति पर पड़ रहा है। विशेष रूप से युद्ध से संबंधित मैनुफैक्चरिंग उद्योगों में इसे गहराई से महसूस किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप नागरिक उद्योगों

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- अमेरिका ने एक तरफ तो यूक्रेन को नाटो के मार्फत हथियार सप्लाई करना शुरु किया, साथ ही चीन व हिन्दुस्तान पर सौ प्रतिशत सैकैण्डरी प्रतिबंध टैरिफ लगाने के लिए अमेरिका के सीनेट व कांग्रेस में विधेयक पेश किया है।
- अमेरिका का मानना है कि चीन व भारत, रूस से अरबों डॉलर का ऑयल खरीद रहे हैं और इस खरीद के जोर पर ही रूस, यूक्रेन से युद्ध करने की ताकत व हिम्मत दिखा रहा था।
- यूक्रेन युद्ध पर रूस का सीधा खर्चा 300 अरब डॉलर आता है तथा विदेशों में रूस की सम्पत्ति को पश्चिमी व यूरोपीय देशों ने ''फ्रीज़ कर रखा है। अतः इन सम्पत्तियों को बेचकर भी रूस युद्ध का खर्चा नहीं निकाल सकता तथा कई पश्चिमी देशों ने तो यह सुझाव तक दिया था, हाल ही में, कि रूस की इन सम्पत्तियों को बेचकर यूक्रेन को पुनः पैरों पर खड़ा करने पर यह पैसा लगाना चाहिए।
- रूस को विश्वास था कि अमेरिका यूक्रेन से दूर होगा तथा आपसी मतभेदों के कारण नाटो के घटक कभी एक नहीं हो पायेंगे।
- पर, धीरे-धीरे रूस के दोनों अंदाज़ गलत साबित हो रहे हैं।